



संपादकीय

ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵਡਿਆਂ ਔਰ ਚੁਨਾਵ

एक ओर सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहले फ्री योजनाओं के खिलाफ इस याचिका पर विचार कर रहा है कि क्यों न फ्री का प्रलोभन देने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी जाए? दूसरी ओर कर्नाटक के चुनाव से पहले कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही कुत्सित प्रयासों में जुटे रहे हैं। कग्रिस, आम आदमी पार्टी और जद एस जैसे राजनीतिक दल मुफ्त वादों के जरिए चुनावी लोकतंत्र की नींव को हिलाने में लगे रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इसके पक्षधर रहे हैं कि चुनावों से पहले मुफ्त रेवड़ीयों के बाद करने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। क्योंकि इसके मूल में जनता का हित नहीं, बल्कि कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ ही छिपे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की गई लोकलुभावन घोषणाएं राज्य की अर्थ व्यवस्था पर भारी पड़ सकती हैं। कर्नाटक बेशक अमीर राज्य है, फिर भी उसकी प्रतिबद्ध देनदारियां इतनी हैं कि चुनावी वादों के नाम पर खैरत बांटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने एक साथ कई बातों पर गंभीरता से विचार करने को बाध्य किया है। भारत के भविष्य की दृष्टि से इसमें एक प्रमुख मुद्दा है लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम पर जनता को मुफ्त वस्तुएं और सेवाएं देने की घोषणाएं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली में चुनावी विजयों की दृष्टि से इसका सर्वाधिक चतुर उपयोग किया है। इसे ही विस्तारित करते हुए पंजाब तक ले गए और वहां भी शानदार विजय का सेहरा उनकी पार्टी के सिर बंधा। यहां इन घोषणाओं और वायदों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ देश के सामने है। साफ दिख रहा था कि दूसरी पार्टियां भी धोर-धीरे 'आप' का अनुसरण कर रही हैं।

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने से लेकर राशन, बिजली सहित ऐसे वायदे किए जो अर्थव्यवस्था के लिए क्षतिकारक हैं। संयोग से उसे विजय प्राप्त हुई। कर्नाटक में उसने ज्यादा विस्तार किया है। यह तो नहीं कह सकते कि भाजपा इस दौड़ में बिल्कुल शामिल नहीं थी। किंतु पुरानी पेंशन योजना की मांग को पूरी ढृता से उसने खारिज किया। भारत की अर्थव्यवस्था और भविष्य की दृष्टि से यह बिल्कुल सही स्टैंड है। किंतु कर्नाटक में उसने भी कांग्रेस के समानांतर जनता को कुछ वस्तुएं और सेवाएं मुफ्त देने की घोषणा की। हमारे देश के ज्यादातर नेता, एक्टिविस्ट, जिनको भारत राष्ट्र के भविष्य की कल्पना नहीं, जो बड़ी कल्पनायें नहीं करते, जो देश, मूल मुद्दों और आम लोगों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को समझने में सक्षम नहीं और उनका परिश्रमसाध्य समाधान नहीं दे पाते वे अपने को गरीब समर्थक साबित करने के

लिए ऐसे ही राज्य द्वारा मुफ्त दान की प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। स्वाभाविक ही इस अंधी दौड़ में जो पार्टियां या व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा होंगा, वह आज के हल्ला बोल माहौल में गरीब विरोधी और पूँजीपतियों, कॉर्पोरेट का दलाल और समर्थक तक करार दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं देश में किसी मुफ्तखोरी की अनुमति नहीं दे सकता। उनका स्पष्ट कहना था कि शारीरिक परिश्रम के बगैर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलना चाहिए। वास्तव में अगर गहराई से देखें तो राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त दान संबंधी घोषणायें और कदम देश के सामूहिक मानस को भिखारी बना देना है। जिस व्यक्ति, समाज और देश के अंदर यह भाव और व्यवहार नहीं है कि अपने समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों, चुनौतियों को स्वयं के संकल्प और परिश्रम से निपटा जाएगा तो वह व्यक्ति, समाज और देश कभी सशक्त व स्वाबलंबी नहीं हो सकता। एक बार समाज को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की मुफ्तखोरी का स्वाद लग गया तो परिश्रम कर स्वयं को सक्षम बनाने का संस्कार नष्ट हो जाता है। उसमें उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। इस विचार और व्यवहार का प्रभाव देखिए कि जिनके के लिए कुछ किलो राशन, कुछ यूनिट बिजली या कुछ लीटर पानी का व्यय मायने नहीं रखता वह भी इससे प्रभावित होते हैं। कई चुनाव परिणामों विशेषकर दिल्ली, पंजाब आदि चुनाव परिणामों का निर्क्षण तो यही है। वैसे भारत में मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी खजाने से मुफ्त दान का लंबा इतिहास है किंतु इसकी शुरूआत लोग दक्षिण के आंध्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों से मानते हैं। वहां मुफ्त चावल से लेकर कलर टीवी, केबल कनेक्शन, मोबाइल तक देने की घोषणाएं हुईं और दी गईं। केंद्र और राज्यों को आय के अनुरूप ही कल्याण और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए खर्च करना है। इस तरह के मुफ्त दान और एक वर्ग को खुश करने के लिए पैंशन आदि बढ़ाई तो उसका असर समूची अर्थव्यवस्था पर होता है और दूसरे समूह भी इसकी मांग करते हैं। इससे विकास की नीतियां और कार्यक्रम प्रभावित होते हैं और व्यवहार में आम लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में भी कटौती करनी पड़ती है। तो राजनीतिक दलों के लिए भी लंबे समय तक के लिए यह लाभकारी नहीं हो सकता। लोगों को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप सांस्कृतिक शैक्षणिक धार्मिक सामाजिक परिवेश सुरक्षा का वातावरण और विकास चाहिए, और न होने पर वह किसी पार्टी को सत्ता से हटा सकते हैं। एनटी रामाराव के नेतृत्व में ही तेलुगु देशम पार्टी की चुनाव में बुरी तरह पराजय हुई। अकाली दल ने भी पंजाब में लोगों को मुफ्त में काफी कुछ दिया, लेकिन यह उसकी सत्ता की स्थाई गारंटी नहीं बन सका। इसके विपरीत गुजरात में भाजपा लगातार 1995 से सत्ता में है। वहां के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त घोषणाओं को स्वीकार नहीं किया। ये उदाहरण राजनीतिक दलों के लिए सीख होनी चाहिए।

कर्नाटक का सदृश : लोकतंत्र में काइ अजय नहीं हाता

सदाचार से ह कोंग्रेस ने तृतीय के ये संदेश बताते हैं कि यह पार्टी भविष्य में भी जनहित की सकारात्मक राजनीति ही करेगी। कांग्रेस यह कभी नहीं भूल सकती कि देश की जनता ने लड़कर आजादी हासिल की और लाखों कुर्बानियों के बाद एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजेशी भगवत् का निर्माण ह था है। देश

समावेशा भरत का निमाण हुआ है। दरा का यह गैरवशाली इतिहास ही कांग्रेस की विरासत है।
कर्नाटक की जनता ने पिछले 34 साल का सबसे बड़ा जनादेश देकर 135 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस को राज्य की सत्ता सौंपी है। इसके पहले 1989 में कांग्रेस को 178 सीटें मिली थीं। इस ऐतिहासिक बहुमत ने भारतीय राजनीति के कई मिथ्क तोड़े हैं तो नई अवधारणाएं

दूसरा
कर्नाटक का चुनाव भाजपा 3
बीच दोतरफा चुनाव बन गय
ने तमाम भटकाने वाले भाव
भड़काऊ मुद्दों को हवा दी, ते
कांग्रेस ने जनता के असली मु
ध्यान केंद्रित किया। हर वर्ग
उनकी समस्याएं जानी गई,
समाधान की गारंटी जनता के
गई और जनता ने भरोसा किय

कर्नाटक चनाव ने मजबूती से यह स्थापित किया। महंगाई से बढ़ती आवासीय में कंप्रेस ने सामाजिक-लोकतांत्रिक एजेंडे पर चुनाव लोकतांत्रिक एजेंडे पर चुनाव किया। महंगाई से बढ़ती आवासीय में कंप्रेस ने सामाजिक-

कर्नाटक : दागी विधायकों की बढ़ती संख्या

डॉ. अंजीत रानादे
राजनेता प्रविशोध की राजनीति के बारे में
शिकायत करते हैं जहां सत्तारूढ़ दल विषयकी
सदस्यों के खिलाफ झुटे मामले दर्ज करते हैं।
न्यायमूर्ति शाह समिति ने 2014 की सुधार
संबंधी सिफारिशों में ऐसी संभावना के
दृष्टिकोण से इन विधायिका के विवरण दिए।

खिलाफ सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट किया है। अब समय आ गया है कि मतदाताओं को इस बात पर जोर देना चाहिए कि प्रत्याशियों के बारे में केवल आपराधिक मामलों का खुलासा पर्याप्त नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पिछले 34 वर्षों में सबसे शानदार विजय है। सीटों की संख्या और वोट शेयर दोनों मामलों में साढ़े तीन दशकों के बाद यह रिकॉर्ड टटा है। यह एक निर्णायिक और व्यापक जनदेश है जिसमें रिकॉर्ड मतदान (72 प्रतिशत) भी हुआ है। इस शानदार जीत में योगदान देने वाले कारणों और खिलाड़ियों का विश्लेषण अंतहीन होगा। क्या यह सत्ता विरोधी लहर का गंभीर मामला था? कर्नाटक में 1985 के बाद किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं की है। क्या यह '40 प्रतिशत कमीशन' के नारे द्वारा कव्या किए गए भ्रष्टचार के खिलाफ धृणा के कारण था? क्या यह धार्मिक भावनाओं को छोड़ने वाले मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण था? क्या यह नफरत फैलाने वाले भाषणों के कारण मतदाता की नारजी थी? ये सभी नकारात्मक प्रेरक कारक हैं। उन सकारात्मक प्रेरकों के बारे में क्या जो इस जीत का कारण बने? क्या ये पांच गारंटीयां थीं जिनका कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लेख किया गया है? ये मुफ्त बिजली, न्यूनतम आय की गारंटी, मुफ्त भोजन और मुफ्त बस पास तथा बेरोजगारी बीमा के बारे में हैं। इनमें से कुछ वादे मुफ्त की तरह लगते हैं और कुछ सामाजिक सुरक्षा की तरह के हैं। बाद वाले आश्वासनों की आवश्यकता है जबकि पहला वादा परेशानी भरा है। कुल मिलाकर उत्तरक कारकों के बारे में हाने वाली यह बहस कभी भी निर्णायिक नहीं होगी। सभी घटक निश्चित रूप से कुछ हद तक मायने रखते थे और

3 4



पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। साल 1999 में न्यायमूर्ति जीवन रेडी के नेतृत्व में 15वें विधि आयोग की 170 वीं रिपोर्ट में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किए थे। फरवरी, 2014 में न्यायमूर्ति एसी शाह के नेतृत्व वाले 20वें विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में आपाराधिक उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए बहुत विस्तृत प्रस्ताव शामिल थे। इससे काफ़ पहले अक्टूबर 1993 में गृह सचिव एनएस वोहरा की अध्यक्षता वाली एक समिति राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम से कम 1990 के दशक की शुरूआत से राजनीति में आपाराधिक दाग वाले प्रत्याशियों का मुद्दा हर किसी के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसके बावजूद आपाराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की चुनाव में हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसी बात है जो संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी देखी जा रही है। यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि लोग आपाराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनते रहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। पिछले महीने ही गैंगस्टर से राजनेता बने एक व्यक्ति और उसके भाई की पुलिस हिरासत के दौरान टीवी कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड गलत था। न्यायेतर हत्याओं और न्यायेतर सक्रियता की निंदा की जानी चाहिए लेकिन चिंता की बात यह भी है कि वह व्यक्ति एवं बार संसद का सदस्य था और पांच बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का। राजनीति को सामने करने की समस्या के दो पक्ष हैं। पहला, आपूर्ति पक्ष और दूसरा है मांग पक्ष। बाद के पक्ष का मतलब है कि मतदाताओं को स्वच्छ उम्मीदवारों को चुनने की जरूरत है। दाग वाले राजनेताओं की मांग कम होनी चाहिए। मतदाताओं को आपाराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को ढूका से अस्वीकृत कर देना चाहिए। हालांकि आपूर्ति की समस्या भी है। अक्सर मतदाताओं के पास मतपत्र सूची

© 2013 Pearson Education, Inc.

इको सिस्टम के लिए जरूरी है जैव विविधता संरक्षण

जीव-जंतु तथा पेड़-पौधे भी मनुष्यों को ही भाँति धरती के अभिन्न अंग हैं लेकिन अपने निहित स्वार्थों तथा विकास के नाम पर मनुष्य ने न केवल वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को बेदर्दी से उड़ाड़ने में बड़ी भूमिका निर्भाइ है और वनस्पतियों का भी तेजी से सफाया किया है। धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त उन सभी चीजों का आपसी संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है, जो उसे प्राकृतिक रूप से मिलती है। इसी को परिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी कहा जाता है लेकिन चिंतनीय स्थिति यह है कि धरती पर अब वन्य जीवों तथा दुर्लभ वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों का जीवनचक्र संकट में है। वन्यजीवों की असंख्य प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कागार पर हैं। पर्यावरणीय संकट के चलते जहां दुनियाभर में जीवों की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने से वन्य जीवों की विविधता का बड़े स्तर पर सफाया हुआ है, वहीं हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर भी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यही स्थिति वनस्पतियों के मामले में भी है। वन्य जीव-जंतु और उनकी विविधता धरती पर अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का आधार रहे हैं। वन्य जीवन में ऐसी वनस्पति और जीव-जंतु सम्मिलित होते हैं, जिनका पालन-पोषण मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता। आज मानवीय क्रियाकलापों तथा अतिक्रमण के अलावा प्रदूषण वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण भी दुनियाभर में जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों के

£ - λ - g -

प्रजातया का भा आस्तत्व मट रहा ह। जीव-जंतुओं तथा पेड़-पौधों की विविधता से ही पृथ्वी का प्राकृतिक सौन्दर्य है, इसलिए भी लुप्तप्रायः पौधों और जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों की उनके प्राकृतिक निवास स्थान के साथ रक्षा करना पर्यावरण संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। इसीलिए पृथ्वी पर मौजूद जीव-जंतुओं तथा पेड़-पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसम्बर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने की शुरूआत की गई थी। इस

एक गए था। दरअसल 22 मई 1992 को नैरेबी एक्ट में जीव विविधता पर अधिसमय के पाठ को स्वीकार किया गया था, इसीलिए यह दिवस मनाने के लिए 22 मई का दिन ही निर्धारित किया गया। धरती पर पेड़-पौधों की संख्या बड़ी तेजी से घटने के कारण अनेक जानवरों और पक्षियों से उनके आशियाने छिन रहे हैं, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ रहा है।
पर्यावरण विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि यदि इस ओर जल्दी ही ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में स्थितियां इतनी खतरनाक हो जाएंगी कि धरती से पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त होकर सदा के इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन

बढ़ती जरूरतों और सुविधाओं की पूर्ति के लिए विकास आवश्यक है लेकिन यह हमें ही तय करना होगा कि विकास के इस दौर में पर्यावरण तथा जीव-जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न न हो। अगर विकास के नाम पर वनों की बड़े पैमाने पर कार्टाई के साथ-साथ जीव-जंतुओं तथा पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे और ये प्रजातियां धीरे-धीरे धरती से एक-एक कर लुप्त होती गई तो भविष्य में उससे उत्पन्न होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना हमें ही करना होगा। बढ़ती आबादी तथा जंगलों के तेजी से होते शहरीकरण ने दरअसल मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया है कि वह प्रकृति प्रदत्त उन साधनों के स्रोतों को भूल चुका है, जिनके बिना उसका जीवन ही असंभव है। आज अगर खेतों में कीटों को मारकर खाने वाले चिड़िया, मोर, तीतर, बटेर, कौआ, बाज, गिद्ध जैसे किसानों के हितैषी माने जाने वाले पक्षी भी तेजी से लुप्त होने के कगार हैं तो हमें आसानी से समझ लेना चाहिए कि हम भयावह खतरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। जैव विविधता की समृद्धि ही धरती को रहने तथा जीवनयापन के योग्य बनाती है, इसलिए लुप्तप्रायः पौधों और जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों की उनके प्राकृतिक निवास स्थान के साथ रक्षा करना पर्यावरण संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है।

(लखक वाइ पत्रकार तथा पायावरण मामलों के जानकार हैं और पर्यावरण पर बहुचर्चित पुस्तक प्रदूषण मत्त सांसे लिख चुके हैं)

बाबा बागेश्वर के बूत लङ्ग 2024 का चुनाव?

बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र की ओर
मुऱ्डकर नहीं देखते। नगापुर में
श्रीराम चरित्र-चर्चा का आयोजन
हुआ था। इस दोरान अंधविद्धा
उम्मूलन समिति के श्याम मानव
बाबा बागेश्वर पर जातू-टोने और
अंधविश्वास फैलाने का आरोप
लगाया था। चुनौती दी कि हमारे
चुने हुए दस लोगों में किसी के
मन की बात पर्चा में लिख कर दें
दो। बागेश्वर वहां से निकल लिये
चुटिया को झटका देते हुए धीरेंद्र
शास्त्री बोले, 'भारत के सबसे
महंगे धरम गुरु हम ही हैं।
वर्तमान में। एक सी-आर तो
चाहिए ही चाहिए, कथा की।'
यूट्यूब का यह वीडियो किलप
फेक नहीं है। मध्यप्रदेश के
छतरपुर स्थित बागेश्वर घाम के

रास्ता। एक सो-आज का माराय हुआ, एक करोड़ रुपए। इस देश के आम आदमी के अकाउंट में एक करोड़ आ जाए, तो सबसे पहले उसे आयकर विभाग में उसका एक प्रतिशत जमा करना होता है। साल भर बाद टैक्स रिटर्न में उसका ब्योरा भरिये। बाबाओं को इस झंझट से सरकारों ने मुक्त कर रखा है। करोड़ों की चल अचल संपत्ति का कोई हिसाब-किताब नहीं देना है। बाबागिरी से चोखा धंधा आज की तारीख में कोई और हो, तो बता दीजिएगा। बाबागिरी के लिए डिग्री-डिल्पोमा की कोई आवश्यकता नहीं। बस बोलने आना चाहिए। जो जितना अच्छा बोलेगा, उतना ही शानदार बेचेगा। यही मूल मंत्र है, इस धंधे का।

विदेश संदेश

युद्ध में दोनों पैर गंवाने वाले पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक ने माउंट एवरेस्ट फ़तह कर इतिहास रचा

काठमांडू। दोनों पैरों से अशक्त एक जांबाज पूर्व ब्रिटिश ने दुनिया के सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का फ़तह कर इतिहास रचा दिया। यह कौटुम्बिन रूपरित करने वाले ही बुधगार (43)



कृत्रिम पैरों से इस चोटी पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह जानकारी नेपाल पर्यटन विभाग के एक वैरिष्ट अधिकारी ने दी। इस अधिकारी ने कहा कि पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक हीरि बुधगार अफगानिस्तान में 2010 में युद्ध लड़ते हुए दोनों पैरों से अशक्त हो गए थे। उन्होंने दोपहर 8848.86 मीटर ऊँची पर्वत चोटी का फ़तह की।

नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत का मंत्रिमंडल विस्तार

काठमांडू। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सुदूर पश्चिम प्रांत के प्रमुख से आज तीन मंत्रियों और एक राज्य मंत्री ने शपथ ली। इन मंत्रियों में नेपाली कांग्रेस



के एक और सीपीएन-एकीकृत माओवादी केंद्र के दो मंत्री और एक राज्य मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री काल बहादुर शह सीपीएन-यूपसी के हैं। उन्हें तीन महीने पहले मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। नेपाल में केंद्र सरकार में सत्ता संस्कृत के बाद प्रांतों में भी बदलाव आया है। 7 प्रांतों में से केवल कोशी प्रांत में सीपीएन-यूपसी के नेतृत्व वाली सरकार है। शेष 6 प्रांतों में सरकार को श्रीनिवास के लिए रखाया हुआ था।

हिन्द प्रशांत क्षेत्र की सफलता और सुरक्षा पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण : पीएम

हिंदोशिमा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में जापान के हिंदोशिमा शहर में हुए परमाणु हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए हिंदोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय में रविवार को पुष्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रॉफी का बाद लापता हो गया, जिसके बाद उनके परिवारवालों ने उसकी स्थिति का ध्यान देने के लिए पहुंचने के बाद और एक राज्य मंत्री ने शपथ ली। इन मंत्रियों ने एक बयान में जी-7 सम्मेलन के लिए जापान के लिए चोटी पर पहुंचने वाले दोनों नेताओं की सम्मलन से इतर

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध के समाधान के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे

टोक्यो। जापान के हिंदोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध दुनिया का एक बड़ा मुद्दा है। वे इसे सिफ अथवास्था और राजनीति का मुद्दा नहीं मानते, उन्हें लिए हर मानवता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भारत और वे स्वयं भी युद्ध की समस्या के समाधान के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ़ास के राष्ट्रपति एमेनुपल मैकों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस



दौरान बैस्ट्रिल दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी फ़ास यात्रा पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत-फ़ास सम्बंधों में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम एवं वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्रीटी कर संयुक्त राष्ट्र महासभिय के साथ हुई अपनी बातचीत को शानदार कराया गया। जर्मनी के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों पर चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सम्बंधों में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम एवं वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्रीटी कर संयुक्त राष्ट्र महासभिय के साथ हुई अपनी बातचीत को शानदार कराया गया।

जर्मनी के साथ द्विपक्षीय सम्बंधों पर चर्चा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की है लेकिन अभी भी उनके पास चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पीएम मोदी जून में

माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय मूल का सिंगापुरी पर्वतारोही लापता

बाशिंगटन। भारतीय मूल का एक सिंगापुरी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद लापता हो गया, जिसके बाद उनके परिवारवालों ने उसकी स्थिति का ध्यान देने के लिए पहुंचने वाले दो मंत्री की है। चेंज डॉट ओआरजी की बेबसाइट में दाखिल की गई एक याचिका के अनुसार श्रीनिवास सैनी दत्तत्रेय एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए पिछले महीने ही सिंगापुर से नेपाल के लिए रखाया हुआ था।

उनके चर्चेरे भाई ने बताया कि चोटी से नीचे उतरते समय श्रीनिवास की शीतदंश और चार्चाई की वजह से वह अपने समझ से बिछड़ गया और 8000 मीटर चौटी की क्षेत्र में रह गया। सिंगापुर की एक टीवी चैनल ने भरत के बावले से बताया कि शेराओं की एक टीम शनिवार को श्रीनिवास के लिए तलाशी



39 वर्षीय श्रीनिवास रियल एस्टेट कंपनी 'जोस लैंग लासेस' में कार्यकारी निदेशक है। एक अप्रैल को वह माउंट एवरेस्ट के लिए नेपाल रखा हुए थे और चार जून को वह स्वदेश लौटने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

श्रीनिवास ने आखिरी बार अपनी पत्नी का शक्तिवार को सदेश भेजा था। भरत ने बताया कि उनके परिवार सबैधित सरकार से लापता हो गया।

भरत ने बताया कि श्रीनिवास का परिवार हालांकाने के लिए खबर दी थी। श्रीनिवास का पूरा परिवार नई दिल्ली में सिंगापुर

श्रीनिवास ने आखिरी बार अपनी पत्नी का लोकप्रियता के कायल हो गए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन तो प्रधानमंत्री मोदी के इन्हें एप्रैल से लोकप्रियता के बात करने वाले हैं।

'मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए'

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तरह से पीएम मोदी को बताया कि उनके परिवार से लोकप्रियता के बाबत लगते हैं।

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पीएम मोदी को बताया कि उनके परिवार से लोकप्रियता के बाबत लगते हैं।

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी से ये भी कहा कि 'उन्हें पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए'

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने भारतीय अपेक्षाकृतियों में जापानी अल्बानीज ने भी पीएम मोदी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पीएम मोदी जून में

सभी को शामिल नहीं कर पाएगे। अल्बानीज ने अपने भारत दौरे को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जो बाइडन से ज्ञात हो गए हैं। अब उनके बाबत लगते हैं। बता दें कि पीएम मोदी का बायोडेटिंग यूपसी

का सामना करना हो गया।

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के इन्हें एप्रैल से लोकप्रियता के बाबत लगते हैं।

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

जापान में क्राड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी का बायोडेटिंग ले लेना चाहिए

अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। जो बाइडन ने पीएम मोदी का बायोडेटिंग ले लेना